हिंदी दैनिक

न्यूज़ वायरस

वर्ष : 11 अंक : 96 | देहरादून, शनिवार, 01 अक्टूबर, 2022 | मूल्य : एक रुपया | पृष्ठ : 08

कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को 3 करोड़ सहायता राशि का डिजिटल हस्तांतरण 3

साइबर सुरक्षा तंत्र एवं इंटेलिजेंस को और अधिक मजबूत करे विभाग : मुख्यमंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 30 सितंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को साइबर सुरक्षा तंत्र एवं इंटेलिजेंस को और अधिक मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि जन समस्याओं एवं जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाना एवं जिला स्तर पर हो सकता है, वे अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय एवं शासन स्तर पर न आयें। उन्होंने कहा कि पुलिस का आम जन के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, लेकिन असामाजिक गतिविधियों पर गहनता से नजर रखी जाए एवं संबंधितों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए।मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि ड्रोन का बेहतर उपयोग भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

देहरादून , 1 अक्टूबर , मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में गृह विभाग की समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को साइबर सुरक्षा तंत्र एवं इंटेलिजेंस को और अधिक मजबूत किए जाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि जन समस्याओं एवं जन शिकायतों का त्वरित समाधान हो। मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि पुलिसिंग व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाने के लिए टीम वर्क से कार्य किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाए कि जिन कार्यों का समाधान थाना एवं जिला स्तर पर हो सकता है, वे अनावश्यक रूप से पुलिस मुख्यालय एवं शासन स्तर पर न आयें। उन्होंने कहा कि पुलिस का आम जन के साथ अच्छा व्यवहार होना जरूरी है, लेकिन असामाजिक गतिविधियों पर गहनता से नजर रखी जाए एवं संबंधितों पर सख्त कार्रवाई भी की जाए। राज्य में स्मार्ट पुलिसिंग व्यवस्था के लिए आधुनिक तकनीक का अधिक से अधिक इस्तेमाल किया जाए।मुख्यमंत्री श्री धामी ने कहा कि ड्रोन का बेहतर उपयोग भीड़ प्रबंधन, ट्रैफिक मैनेजमेंट एवं आपदा प्रबंधन में कैसे किया जा सकता है, इस ओर विशेष ध्यान दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने अंकिता भंडारी के परिजनों से घर पर जाकर की मुलाकात

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

पौड़ी, 30 सितंबर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पौड़ी के श्रीकोट में अंकिता भंडारी के परिजनों से मुलाकात की और भरोसा दिलाया कि पूरी सरकार उनके साथ खड़ी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि फास्ट ट्रेक कोर्ट में सुनवाई कराते हुए अंकिता के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पौड़ी जनपद अंतर्गत श्रीनगर के डोभ श्रीकोट गांव पहुँचे और अंकिता के परिजनों से भेंट कर उन्हें ढांढस बंधाया। मुख्यमंत्री ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मामले की जांच को डीआईजी पी.रेणुका देवी के नेतृत्व में एक एसआईटी टीम गठित की गई है जिसने अपनी जांच प्रारंभ कर दी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस हत्याकांड के तीनों आरोपितों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और जांच में जिन भी लोगों की भूमिका संदेह के दायरे में है उन पर भी कानून सम्मत कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। इस दौरान उन्होंने पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता की धनराशि भी प्रदान की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री डॉ. धन सिंह रावत, जिलाधिकारी डॉ. विजय कुमार जोगदंडे, SSP यशवंत सिंह चौहान, SDM आकाश जोशी आदि भी उपस्थित रहे

प्रदेश में आज 139 केंद्रों में होगी उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा

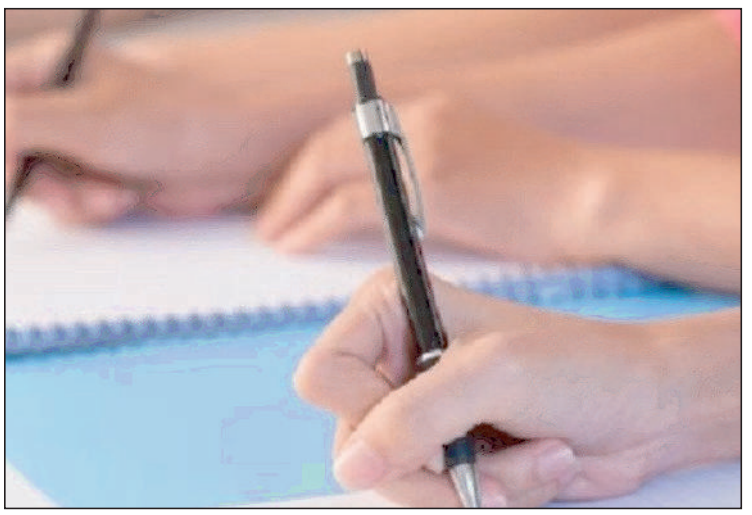

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 30 सितंबर। प्रदेश में शुक्रवार को 29 शहरों के 139 केंद्रों में उत्तराखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। विद्यालयी शिक्षा परिषद की सचिव नीता तिवारी के मुताबिक बिना प्रवेशपत्र और आईडी के किसी भी परीक्षार्थी को परीक्षा में शामिल नहीं होने दिया जाएगा।

शिक्षा परिषद की सचिव के मुताबिक टीईटी प्रथम पाली की परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होगी, जबकि द्वितीय पाली दोपहर 2:00 बजे से 4:30 बजे तक होगी। परीक्षार्थियों को मोबाइल सहित किसी भी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लेकर आना पूरी तरह से प्रतिबंधित होगा। परीक्षा कक्षों में कक्ष निरीक्षकों एवं परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को भी मोबाइल ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा के सफल एवं शांतिपूर्ण संचालन के लिए हर शहर में एक अधिकारी को नोडल अधिकारी तैनात किया गया है। हर परीक्षा केंद्र में एक पर्यवेक्षक की भी तैनाती की गई है। जो पूरे परीक्षाकाल में परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण करेंगे। जिला प्रशासन की ओर से भी शहरों को सेक्टर में बांटकर सेक्टर मजिस्ट्रेटों की तैनाती की गई है। यूटीईटी प्रथम में 29545 एवं यूटीईटी द्वितीय में 30755 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होंगे।

आज से बदल गया डेबिट-क्रेडिट कार्ड से पेमेंट का तरीका, आप भी जान लीजिये

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 30 सितंबर। बैंक ग्राहकों को वित्तीय धोखाधड़ी से बचाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड के जरिए ऑनलाइन पेमेंट के नए नियमों के बारे में बताया था, जो अगले महीने यानी 1 अक्टूबर 2022 से लागू होंगे। अगर आप भी पेमेंट के लिए कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो यह खबर आपके काम की है क्योंकि इस नियम से ऑनलाइन पेमेंट का तरीका बदल जाएगा।

क्या है कार्ड टोकनाइजेशन ?

आरबीआई के अनुसार, टोकननाइजेशन वास्तविक कार्ड की जानकारी को 'टोकन' नामक एक वैकल्पिक कोड के साथ बदलेगा। यह टोकन अद्वितीय होगा। यह टोकन ग्राहक के कार्ड डेटा का प्रतिनिधित्व करता है, जो व्यापारी के पेमेंट सिस्टम में सेव किया जाता है और लेनदेन को संसाधित करता है।

कब से लागू होगा नियम?

इस साल जून के अंत में भारतीय रिजर्व बैंक ने डेबिट और क्रेडिट कार्ड टोकनाइजेशन की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 1 अक्टूबर 2022 कर दिया था। जबकि पहले यह नियम 1 जुलाई से लागू हो रहा था। ज्यादातर बड़े व्यापारियों ने पहले ही आरबीआई के टोकन मानदंडों का अनुपालन कर लिया है।इस नियम से अब मर्चेंट और पेमेंट गेटवे कंपनी कार्ड पेमेंट के समय आपके कार्ड का डेटा अपने पास सेव नहीं कर पाएंगी। इसके बजाय, उनके पास सेव किए गए टोकन की जानकारी होगी। पहले आपके डेबिट या क्रेडिट कार्ड की जानकारी, जैसे कि 16-डिजिट नंबर, नाम, एक्सपायरी डेट, आदि जो फ्यूचर के पेमेंट के लिए सेव कर ली जाती थी। अब इन्हें एक टोकन से रिप्लेस किया जाएगा। यानी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए अब आपको व्यापारी की वेबसाइट द्वारा टोकन का इस्तेमाल करना होगा।

टोकनाइजेशन से कैसे होगा पेमेंट?

कार्ड धारक टोकन अनुरोधकर्ता द्वारा प्रदान किए गए ऐप पर एक रिक्वेस्ट करके कार्ड का टोकन प्राप्त कर सकता है। टोकन अनुरोधकर्ता कार्ड नेटवर्क को रिक्वेस्ट फॉर्वर्ड करेगा, जो कार्ड जारीकर्ता की सहमति से कार्ड, टोकन अनुरोधकर्ता और डिवाइस के कॉम्बेनिशन के अनुरूप टोकन जारी करेगा।

IIT-रुड़की ने लार में पाए जाने वाले 3 प्रोटीन की पहचान की, दावा किया कि यह स्तन कैंसर की भविष्यवाणी कर सकता है

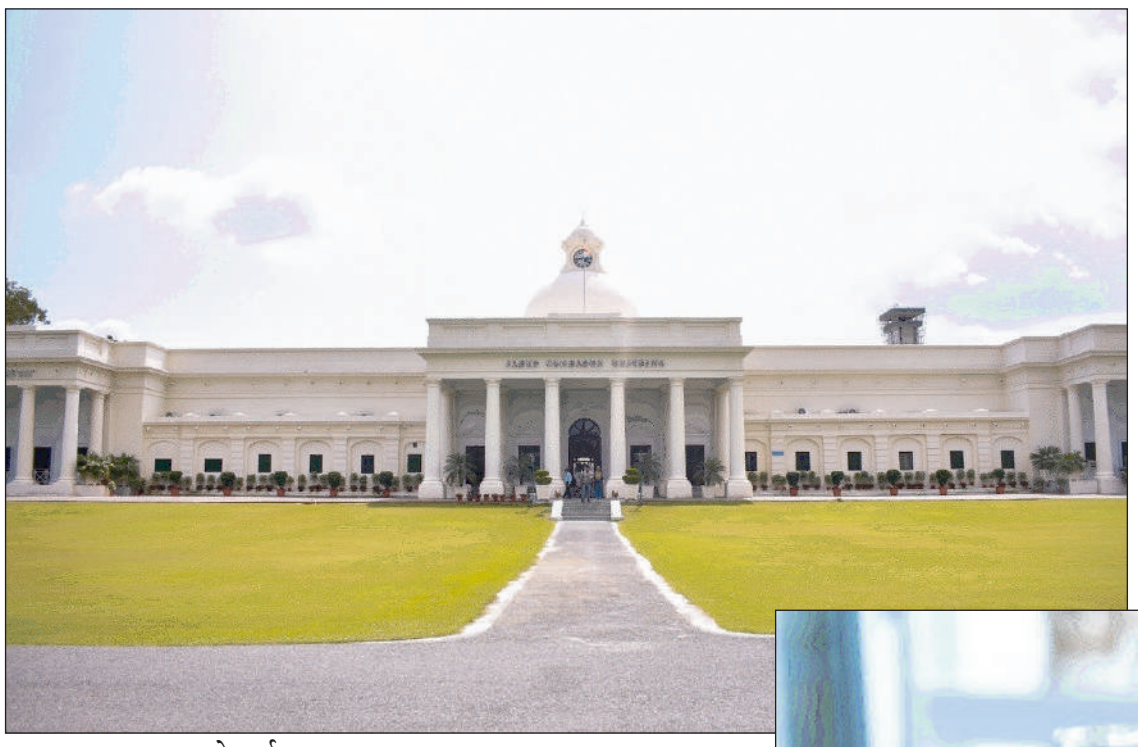

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान-रुड़की के शोधकर्ताओं ने लार में पाए जाने वाले तीन प्रोटीनों की पहचान करने और उन्हें मान्य करने का दावा किया है जो मेटास्टैटिक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर की भविष्यवाणी कर सकते हैं, एक आक्रामक कैंसर जो जल्दी बढ़ता है, सामान्य हार्मोनल प्रतिक्रिया नहीं देता है और HER2-प्रोटीन लक्षित करने वाली दवाएं और उपचार के बाद इसके फिर से शुरू होने की संभावना है। शोधकर्ताओं ने एक ऐसी प्रक्रिया विकसित की जिसके द्वारा लार में टीएनबीसी के लिए बायोमार्कर की पहचान की जा सकती है।

उनके निष्कर्ष पीयर-रिव्यू 'जर्नल ऑफ प्रोटिओमिक्स' के सितंबर अंक में प्रकाशित हुए हैं। इस शोध का नेतृत्व 44 वर्षीय किरण अंबातिपुडी, एसोसिएट प्रोफेसर, बायोसाइंसेज और बायोइंजीनियरिंग विभाग, IIT रुड़की ने किया था, और इसमें उनके डॉक्टरेट छात्र, 26 वर्षीय कुलदीप गिरी और 25 वर्षीय सुदीपा मैती शामिल थे।

शोध के अनुसार, सभी स्तन कैंसर के लगभग 10% से 15% मेटास्टेटिक TNBC हैं। टीम ने स्वस्थ विषयों और कैंसर रोगियों के बीच तीन लार प्रोटीन - लिपोकेलिन -1, एसएमआर -3 बी और प्लास्टिन -2 की मात्रा में अंतर की खोज की।आगे के अध्ययनों ने इन तीन प्रोटीनों से पांच पेप्टाइड्स (प्रोटीन के निर्माण खंड) को अलग कर दिया, जो आक्रामक टीएनबीसी और स्वस्थ विषयों के बीच काफी भिन्न थे। ये पेप्टाइड्स 80% संवेदनशीलता और 95% विशिष्टता के साथ TNBC की उपस्थिति की ओर इशारा कर सकते हैं।टीम की निदान पद्धति लार ग्रंथि के कार्य पर आधारित थी, जो स्तन कैंसर वाले लोगों में बिगड़ा हुआ है। उनकी प्रोटीन संरचना भी बदल जाती है। इस प्रकार, एक प्रभावी बायोमार्कर प्राप्त किया जा सकता है यदि अंतर की पहचान की जा सकती है और मात्रा निर्धारित की जा सकती है, अंबातिपुडी ने कहा।उन्होंने कहा, ₹वर्तमान में, स्तन कैंसर के निदान के लिए बायोप्सी और रेडियोलॉजिकल मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। ये आक्रामक प्रक्रियाएं हैं और आमतौर पर लक्षण प्रकट होने के बाद ही प्रदर्शन किया जाता है, और तब तक उपचार के लिए बहुत देर हो सकती है। स्तन कैंसर के रोगियों की उच्च रुग्णता दर का प्राथमिक कारण देरी से पता लगाना है, और इसके लिए ऐसी तकनीकों के विकास की आवश्यकता है जो न केवल गैर-आक्रामक हैं बल्कि प्रारंभिक अवस्था में कैंसर का पता लगाने के लिए पर्याप्त संवेदनशील हैं। हमारे द्वारा खोजे गए पेप्टाइड मार्कर भविष्य में स्तन कैंसर के निदान के लिए एक शक्तिशाली उपकरण बन सकते हैं।₹टीम ने स्वस्थ विषयों और टीएनबीसी के निदान वाले लोगों से लार एकत्र की। इन लार के नमूनों में प्रोटीन को अलग किया गया और लक्षित मास स्पेक्ट्रोमेट्री द्वारा बहुतायत में परिवर्तन के लिए परीक्षण किया गया। IIT-R के निदेशक प्रोफेसर एके चतुर्वेदी ने कहा, "शोध के निष्कर्ष संभावित रूप से शीघ्र निदान और उपचार में मदद कर सकते हैं। इससे ऐसे रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होगा।

कोविड-19 से प्रभावित बच्चों को 3 करोड़ सहायता राशि का डिजिटल हस्तांतरण

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 30 सितंबर। दिनांक 1 मार्च 2020 से 31 मार्च, 2022 तक की अवधि में कोविड-19 महामारी एवं अन्य बीमारियों से पिता/माता/संरक्षक की मृत्यु के कारण जन्म से 21 वर्ष तक के प्रभावित बच्चों की देखभाल, पुर्नवास, चल-अचल सम्पत्ति एवं उत्तराधिकारों एवं विधिक अधिकारों के संरक्षण हेतु ''मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना'' लागू की गयी है. इस योजनान्तर्गत दिनांक 01 अगस्त, 2021 को ''मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना'' का शुभारम्भ राज्य के अति संवेदनशील मा0 मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री आवास से किया गया। प्रथम चरण में योजनान्तर्गत 1061 बच्चों को माह जुलाई, 2021 की धनराशि का हस्तान्तरण किया गया। योजना में आच्छादित बच्चों को रू0 3,000/- की आर्थिक सहायता प्रतिमाह 01 जुलाई 2021 से 21 वर्ष की आयु तक अनुमन्य की गयी है।

आज लगभग 5000 बच्चों को माह अगस्त एवं सितम्बर, 2022 हेतु कुल रू0 3 करोड़ (प्रति माह रू0 3000/-) की धनराशि का हस्तान्तरण PFMS के माध्यम से सीधे बच्चों के खाते में किया गया। योजनान्तर्गत अभी तक लगभग 5000 बच्चों को आच्छादित किया गया है, जिनको प्रतिमाह रू 3000 की धनराशि माह जुलाई, 2021 से सीधे बच्चों के खाते में हस्तान्तरित कर लाभान्वित किया जा रहा है।

इस दौरान कैबिनेट मंत्री रेखा आर्या ने कहा की सरकार संवेदनशीलता के साथ बच्चों के देखरेख व पुर्नवास के लिये कार्य कर रही है। बच्चों को सभी सरकारी योजनाओं का लाभ मिले, उनके आगे बढ़ने में कोई बाधा या रूकावट ना आये, इसलिये अभिभावक के रूप में सरकार द्वारा सदैव तत्परता के साथ कार्य करते हुये बच्चों के संरक्षण, उनके प्रगति राह में आगे बढ़ने की राह में कोई बाधा ना आये, इसलिये विभिन्न विभागों के साथ बैठक कर समन्वित रूप से बच्चों हेतु महत्वपूर्ण प्रावधान कराये गये है, जिनमे स्वास्थ्य विभाग द्वारा अटल आयुष्मान कार्ड,निशुल्क चिकित्सा उपचार प्रदान करना के साथ तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के नियंत्रणाधीन तकनीकी शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययन हेतु अनुमन्य आरक्षण निशुल्क शिक्षा प्रदान करना है।

इस अवसर पर कार्यक्रम में हरिचन्द्र सेमवाल, सचिव, महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास, प्रदीप सिंह रावत, निदेशक, मोहित चौधरी, मुख्य परिवीक्षा अधिकारी, अंजना गुप्ता, उप मुख्य परिवीक्षा अधिकारी एवं मीना बिष्ट, जिला प्रोबेशन अधिकारी सहित विभागीय अधिकारी और बच्चे उपस्थित रहें।

68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में उत्तराखण्ड को मिला Most Film Friendly State (Special Mention) पुरस्कार

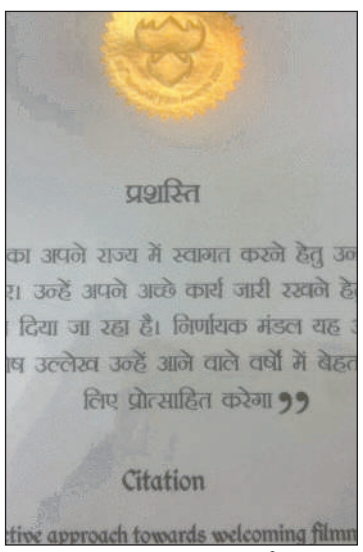

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

नई दिल्ली, 30 सितंबर। विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में भारत के राष्ट्रपति श्रीमती द्रोपदी मुर्मू द्वारा उत्तराखण्ड को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Most Film Friendly State (Special Mention) पुरस्कार प्रदान किया गया। राज्य सरकार की ओर से यह पुरस्कार महानिदेशक, सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी द्वारा प्राप्त किया गया है।

महानिदेशक, सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने कहा कि उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार मिलने से प्रदेश में फिल्मों की शूटिंग को और अधिक प्रोत्साहन मिलेगा। महानिदेशक, सूचना ने कहा कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा फिल्म उद्योग को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिये गये है। राज्य सरकार में फिल्म निर्माता-निर्देशकों के लिए अनुकूल माहौल बनाया गया है, जिसका परिणाम है कि आज उत्तराखण्ड को राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। मुख्यमंत्री श्री धामी द्वारा प्रदेश की फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक बनाया जा रहा है। फिल्म नीति को और अधिक आकर्षक और व्यावहारिक बनाया जा रहा है। इससे राज्य में फिल्म निर्माण क्षेत्र को और अधिक प्रोत्साहित किया जा सकेगा। राज्य में अधिक से अधिक फिल्म निर्माता आ सकेंगे और स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ सकेंगे। राज्य सरकार द्वारा फिल्म नीति को आकर्षक बनाया गया है, जिसमें सिंगल विंडो शूटिंग अनुमति प्रदान किया जाना। अब राज्य में शूटिंग हेतु कोई भी शुल्क नही लिया जा रहा है। नई फिल्म नीति में रुपये 1.5 करोड़ तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। इसके साथ ही शूटिंग अवधि में पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराया जाना शामिल है। क्षेत्रीय फिल्मों को स्थानीय सिनेमाघरों द्वारा सप्ताह में एक शो अनिवार्य रूप से दिखाया जाना है।

महानिदेशक, सूचना एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद बंशीधर तिवारी ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर के इस पुरस्कार के लिए उत्तराखण्ड राज्य का चयन हम सभी के लिए गौरव की बात है। अल्प कार्यकाल में देश के अन्य राज्यों को पीछे छोड़ते हुए उत्तराखण्ड राज्य का इस पुरस्कार के लिए चयन हुआ है। उन्होंने कहा की आगे भी सुविधा और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा ताकि अधिक से अधिक फ़िल्मों की शूटिंग उत्तराखंड में हो सके और उत्तराखंड विश्व पटल पर अपनी उपस्थिति और बेहतर तरीक़े से दर्ज करा सके।

उत्तराखण्ड फिल्म विकास परिषद के नोडल अधिकारी डॉ. नितिन उपाध्याय ने बताया कि उत्तराखण्ड राज्य को 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Most Film Friendly State (Special Mention) का पुरस्कार प्रदान किया गया है। भारत सरकार द्वारा यह पुरस्कार फिल्म उद्योग को आगे बढ़ाने, जिसमें राज्य में फिल्म निर्माण के लिए अनुकूल वातवारण तैयार करना शामिल है। इसके साथ ही फिल्म और कला क्षेत्र को प्रोत्साहन देना एवं बंद पड़े सिनेमा हॉल को फिर से खोलने के लिए प्रोत्साहित करना है। उत्तराखण्ड राज्य को यह पुरस्कार राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है।राज्य में उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा फिल्म निर्माताओं की सुविधाओं के दृष्टिगत आकर्षक फिल्म नीति लागू की गई है। विगत एक वर्ष में राज्य में 150 से अधिक फिल्मों, धारावाहिक, डाक्यूमेंट्री आदि की शूटिंग की गई है। इनमें द कश्मीर फ़ाइल, मीटर चालू, बत्ती गुल, परमाणु, बाटला हाउस, कबीर सिंह, केदारनाथ, नरेन्द्र मोदी, स्टूडेंट ऑफ द ईयर, परमाणु, रागदेश, तड़प, वार, डिस्कवरी चैनल पर प्रसारित कार्यक्रम Man vs Wild आदि कई बड़े नाम भी शामिल है। वर्ष 2017 के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के अन्तर्गत Special Mention Certificate for Film Friendly Environment पुरस्कार प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 में पर्यटन पुरस्कार के अर्न्तगत उत्तराखण्ड राज्य को "राष्ट्रीय फिल्म संवर्धन हितैषी राज्य" का पुरस्कार प्रदान किया गया है। वर्ष-2018 के तहत सर्वश्रेष्ठ फिल्म प्रमोशन फ्रेण्डली स्टेट पुरस्कार-2018, वर्ष-2019 में मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट का प्रथम पुरस्कार-2019 मिला है। इन पुरस्कारों हेतु राष्ट्रीय स्तर पर गठित चयन समिति द्वारा निर्धारित मानकों का परीक्षण कर यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। पुरस्कार हेतु निर्धारितों मानकों के अनुसार विवरण भारत सरकार को प्रेषित की किया जाता है, जिसमें Ease of filming, Infrastructure, सब्सिडी, Database, Marketing and Promotion एवं विगत वर्षों में राज्य में शूटिंग की गई फिल्मों की संख्या का विवरण प्रदान करना होता है।

हरिद्वार पंचायत चुनाव में बीजेपी का पलड़ा भारी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड के हरिद्वार जिले में गुरुवार को त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत की ओर बढ़ रही है। पार्टी ने जिला पंचायत बोर्ड की 44 में से पांच सीटों पर जीत हासिल की है और 15 सीटों पर आगे चल रही है। अब तक घोषित आठ सीटों के नतीजों के मुताबिक बीजेपी ने पांच, बहुजन समाज पार्टी ने दो और कांग्रेस ने एक पर जीत हासिल की है। मतगणना अभी जारी है लेकिन जिला पंचायत में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर सकती है। उसे कुल

20 सीटें मिलने की संभावना है। ब्लॉक और ग्राम पंचायत की 70 फीसदी सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. कुल 316 ग्राम प्रधान सीटों में से 282 सीटों के नतीजे घोषित हो चुके हैं।

इनमें से ज्यादातर सीटों पर बीजेपी समर्थित उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है।छह प्रखंड पंचायतों की अधिकांश सीटों पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने भी जीत हासिल की है। हरिद्वार के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने पंचायत चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन पर खुशी जाहिर की है।

इस गांव के रामलीला में, बेटी ने निभानी शुरू की पुरुषों की भूमिका

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून 30 सितंबर। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री और हरिद्वार के प्रभारी मंत्री सतपाल महाराज ने जनपद में हुए पंचायत चुनाव में भाजपा को मिली प्रचण्ड जीत को जनता के विश्वास, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की नीतियां और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की जीत बताया है। हरिद्वार के प्रभारी मंत्री और प्रदेश के पंचायती राज,मंत्री सतपाल महाराज ने हरिद्वार जनपद में हुए पंचायत चुनाव में जिला पंचायत की 44 सीटों में से 26 सीटों में से अभी तक सर्वाधिक 14 सीटें पर भाजपा को पहली बार मिली बड़ी सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस जीत को भाजपा के प्रति जनता के विश्वास, पार्टी कार्यकर्ताओं की मेहनत, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोक कल्याणकारी नीतियां और प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुशल नेतृत्व की जीत बताया है। आपको बता दें कि त्रिस्तरीय पंचायतों को सशक्त करने के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रयासों को पंचातीराज मंत्री सतपाल महाराज लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में अनेक विकास योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। उसी परिणाम है कि हरिद्वार पंचायत चुनाव में मिली प्रचंड जीत से भाजपा बेहद उत्साहित नजर आ

रही है। पार्टी ने जिले में अब तक हुए चार जिला पंचायत चुनावों में चार से अधिक सीटें नहीं जीती थीं। लेकिन इस बार 14 सीटें जीत कर पार्टी में जबरदस्त उत्साह दिखाई दे रहा है।प्रभारी मंत्री महाराज ने कहा कि जनपद में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान की अधिकांश सीटों पर भाजपा को मिली अपार सफलता इस बात का प्रमाण है कि भाजपा सरकार में ग्रामीण व्यवस्था लोकतांत्रिक रूप से लगातार और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है।

इस गांव के रामलीला में, बेटी ने निभानी शुरू की पुरुषों की भूमिका

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रामलीला में जहां पुरुष महिला पात्रों की भूमिका निभाते थे, आज इसके विपरीत हो रहा है। अब बेटियां पुरुषों की भूमिका निभाने लगे हैं। दशकों से पर्वतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ रही बेटियों ने अब उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ी रामलीलाओं को बचाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली है। पलायन के कारण जब गांवों में पात्रों के खाली होने का संकट आया तो बेटियों ने स्कूलों और खेत खलिहानों के साथ मंच संभाला।

अल्मोड़ा, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल के कई गांवों और कस्बों में बेटियां अब मुख्य किरदार निभा रही हैं।कुछ साल पहले तक रामलीला में महिला कलाकारों का अभिनय भी पुरुषों द्वारा किया जाता था, लेकिन अब लड़कियां भी पुरुषों की भूमिका निभा रही हैं। कर्नाटक खोला की रामलीला, अल्मोड़ा में नंदा देवी, हुक्का क्लब के कई मुख्य पात्र बेटियों के साथ हैं। अब बागेश्वर की कांडा की रामलीला में भी बेटियां नजर आएंगी। बेरीनाग में भी लड़कियों ने रामलीला में अभिनय करना शुरू कर दिया है।एमबीपीजी में समाजशास्त्र की प्रवक्ता डॉ. स्निग्धा रावत ने कहा, पहाड़ की रामलीला में बेटियों के प्रवेश का प्रमुख कारण पलायन है. हालांकि, मैदानी इलाकों में सांस्कृतिक बदलाव भी इसका एक प्रमुख कारण है। रंगमंच के क्षेत्र में लड़कियों का आगे आना सामाजिक बदलाव का संकेत है। नागदेव रामलीला समिति बेरीनाग के अध्यक्ष बलवंत धनिक ने कहा कि पहाड़ों की ओर पलायन एक बड़ी समस्या है. पहले कलाकारों का चयन करना पड़ता था लेकिन अब ऐसा नहीं है। बेटियों के मंच पर आने से रामलीलाओं को नया जीवन मिलेगा। रामलीला समिति के प्रशासक दर्पण सिंह ने कहा, गांव में लोग नहीं हैं, रामलीला के पात्र कहां से आएंगे. ऐसे मौके पर बेटियों ने शिक्षा के क्षेत्र में आकर पहाड़ के सबसे पुराने चबूतरे में नई जान फूंक दी है.

CM धामी के नेतृत्व में रानीपोखरी के नवनिर्मित पुल पर दौड़ने लगी गाड़ियां

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 30 सितंबर। रानीपोखरी के नवनिर्मित पुल का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उद्घाटन किया..... आपको बता दें कि ये नया ब्रिज लगभग 16 करोड़ की लागत से जाखन नदी पर बनाया गया है. इसके पहले पुराना पुल पिछले साल अगस्त महीने में नदी के तेज बहाव में धराशाई हो गया था. इसके अलावा सीएम धामी ने अन्य पुलों का भी लोकार्पण किया.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रानीपोखरी में जाखन नदी पर बने नवनिर्मित पुल का विधिवत पूजा अर्चना कर उद्घाटन किया. लोक निर्माण विभाग ने 16 करोड़ की लागत से पुल का निर्माण किया है. इसके साथ ही सीएम धामी ने 13 करोड़ की लागत से तैयार विकासनगर में लांघा मोटर मार्ग पर शीतला नदी पर बने पुल को भी जनता को सौंपा. इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि रानीपोखरी पुल के गिरने से जनता को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था. यही पुल राजधानी से पूरे गढ़वाल को जोड़ता है.

सीएम धामी ने कहा कि उन्होंने जनता की परेशानी को देखते हुए 6 महीने के भीतर कार्यदायी संस्था को पुल को तैयार करने को कहा और समय रहने पुल का निर्माण भी हो गया. केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड में सड़कों का जाल (Road Connectivity in Uttarakhand) बिछ गया है. चारधाम को जाने वाले मार्ग बेहतर हो गए हैं. यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं.

नए सीडीएस के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना नए कीर्तिमान बनाएगी : ऋतु खंडूडी भूषण

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 30 सितंबर। उत्तराखंड के सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान द्वारा नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉफ का कार्यभार संभालने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूडी भूषण ने उन्हें प्रदेशवासियों की ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं।विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि देश के दूसरे सीडीएस बनने का गौरव एक बार फिर उत्तराखंड के सपूत को प्राप्त हुआ है। उन्होंने कहा की पौड़ी जिले के साथ उत्तराखंड के लिए आज का यह पल गौरवान्वित करने वाला है।

विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि नए सीडीएस के कुशल नेतृत्व में भारतीय सेना सदैव की भांति राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित करेगी'।वह एक उत्कृष्ट अधिकारी हैं जिन्होंने बड़े उत्साह के साथ भारत की सेवा की है। उन्होंने कहा कि देश के नए सीडीएस इंडियन आर्मी को आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनाने की दिशा में काम करेंगे। विधानसभा अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आभार व्यक्त किया है।

हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव

चुनाव जीतकर समर्थकों के साथ लौट रहे नवनिर्वाचित प्रधान की कार पलटी, एक की मौत

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

रुडकी, 30 सितंबर। चुनाव जीतकर समर्थकों के साथ कार से घर लौट रहे नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान की कार पलट गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई वहीं ग्राम प्रधान समेत तीन लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। वहीं, हादसे की सूचना से चुनाव की जीत गम में बदल गई। बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे और जानकारी ली।

बुग्गावाला थाना क्षेत्र के गांव लालवाला खालसा निवासी शमशेर अली ग्राम प्रधान के पद पर खड़े थे। बृहस्पतिवार को परिणाम आने के बाद उन्हें विजयी घोषित किया गया। जीत से उनके समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई। भगवानपुर ब्लॉक से जीत का प्रमाणपत्र लेकर शमशेर अली अपने समर्थकों के साथ कार से गांव लौट रहे थे।

जैसे ही उनकी कार रसूलपुर के पास हाईवे पर पहुंची तो अचानक अगले टायर में पंक्चर हो गया। इससे कार अनियंत्रित होकर हाईवे किनारे खाई में जा गिरी और बिजली के खंभे से टकरा गई। इससे कार के अंदर बैठे सुखपाल सिंह (55) की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं नवनिर्वाचित ग्राम प्रधान शमशेर अली सहित मुनफैद और इमरान घायल हो गए।

सूचना मिलते ही यूपी के फतेहपुर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया। साथ ही शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं, गांव में प्रधान के समर्थकों को हादसे की जानकारी मिली तो खुशी का माहौल गम में बदल गया। एसओ पीडी भट्ट ने बताया कि जहां पर घटना हुई है, वह फतेहपुर थाना क्षेत्र में आता है। वहां की पुलिस ही पूरे मामले में कार्रवाई करेगी।

अंकिता के हत्यारों को मिले सख्त सजा : इ० डीपीएस रावत, पहाड़ी एकता मोर्चा

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

देहरादून, 30 सितंबर। पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इं० डीपीएस रावत ने अंकिता भंडारी हत्याकांड को बेहद दुखद करार देते हुए ऐसे अपराध करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा होने की पीएमओ से मांग की। इं० डीपीएस रावत कहां की जब ऐसे लोगों को कहीं ना कहीं राजनीति में संरक्षण मिलता है तो अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाते हैं और अपनी मनमानी से अपराध करने लगते हैं।

उन्होंने कहा कि पिछले 22सालो से बीजेपी कांग्रेस की सरकार रही है और इनके कार्यकाल में गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के पहाड़ी जिलों में भू माफियाओं ने अपने पैर जमाने शुरू किए जिसका खामियाजा आज पहाड़ के लोग भुगत रहे हैं अगर इन दोनों सरकारों की साफ नियत होती तो पहाड़ों में शक्त भू-कानून लगाते तो आज यह प्रदेश इन सभी समस्याओं से वंचित रहता आज बाहरी प्रदेश के भू-माफिया पहाड़ों में कई हजारों नाली जमीन खरीद चुके हैं और प्रदेश की सरकार केवल मौन व्रत कर बैठी है सरकार को सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इन भू-माफिया के खिलाफ और इससे उत्तराखंड के पर्यावरण को भी काफी नुकसान हो रहा है हमारे जंगल जमीन पानी बर्बाद हो रहे हैं।

इं० डीपीएस रावत कहां कि अंकिता हत्याकांड के अपराधियों के खिलाफ सक्त व निष्पक्ष तरीके से सीबीआई से जांच होनी चाहिए और ऐसी नजीर पेश करनी चाहिए कि ऐसी मानसिकता के लोग घिनौने अपराध करने से पहले सौ बार सोचे। हमें उत्तराखंड राज्य हमारी मातृ शक्ति के बलिदान से मिला है पहाड़ की महिला स्वाभिमानी होती है उसके साथ ऐसी घिनौनी हरकत किसी भी तरह से बाहर के लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते उन्होंने कहा रिजॉर्ट संचालक को लेकर नियम बने उनका यूपी सरकार के तरह सख्ती से पालन होना चाहिए।

पथराव और तोड़फोड़ के पांच आरोपी गिरफ्तार, छह पर मुकदमा दर्ज

हरिद्वार/बहादराबाद, 30 सितंबर। हरिद्वार के बहादराबाद में मतगणना स्थल के बाहर पथराव और तोड़फोड़ करने के पांच आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने कांग्रेसी नेता मुकर्रम अंसारी सहित आठ नामजद और 60 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। फरार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है।

बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय इंटर कालेज रोहालकी में मतगणना के दौरान ग्राम भगतनपुर-आबिदपुर से प्रधान पद की प्रत्याशी रशिया निवासी इब्राहिमपुर, पथरी चुनाव हार गई थीं। वह अपने पति अजमल खान के साथ मतगणना स्थल से बाहर गेट पर आ गई। इसके बाद उनके करीब 60 समर्थकों ने मतगणना अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी थी। मुख्य गेट से करीब 50 मीटर दूर अलीपुर रोड पर लगी बैरिकेडिंग के पास सभी एकत्र हो गए। इसके साथ ही जिला पंचायत सीट से रवि के चुनाव हारने के बाद सराय निवासी कांग्रेसी नेता मुकर्रम अंसारी अपने समर्थकों के साथ बैरिकेडिंग पर एकत्र हो गए। दोनों प्रत्याशियों के समर्थकों ने मतगणना में लगे अधिकारियों और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया। लेकिन पुलिस के साथ गाली-गलौज करते हुए बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। रोकने पर पुलिसकर्मियों पर पथराव कर सड़क पर खड़ी मोटरसाइकिलें तोड़ डाली। जिसमें इंस्पेक्टर बीएल भारती और बहादराबाद एसओ नितेश शर्मा घायल हो गए थे। बहादराबाद थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि अलीपुर रोड स्थित बाग से भागते हुए आरोपी अहसान अली, कुर्बान, साहिब, अशरफ, अनीस निवासीगण निवासी इब्राहिमपुर पथरी को गिरफ्तार कर लिया गया। जबकि फरार रशिया और अजमल निवासी इब्राहिमपुर और मुकर्रम निवासी ग्राम सराय की तलाश की जा रही है। कांग्रेसी नेता सहित आठ नामजद आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज किया है। एसओ नितेश शर्मा ने बताया कि धारा 147, 148, 307, 333, 353, 323, 504, 506, 188, 34 आईपीसी और 3/4 लोक संपत्ति निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया है। जबकि 60 अज्ञात आरोपियों की सीसीटीवी कैमरे से पहचान की जा रही है।

एसपी श्वेता चौबे ने कोतवाली चमोली को दी मॉर्डन पुलिस बैरक की सौगात

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

चमोली, 30 सितंबर। प्रधानमंत्री के स्मार्ट पुलिसिंग विजन के अनुरुप MHA से प्राप्त गाइडलाइन व पुलिस महानिदेशक की परिकल्पना के परिपेक्ष्य में पुलिस अधीक्षक चमोली श्वेता चौबे के निर्देशन में पुलिसकर्मियों की जीवनशैली एवं रहन सहन में गुणात्मक सुधार एवं बेहतर वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से कोतवाली चमोली में वर्षों से जर्जर और पुरानी बैरकों को आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कर स्मार्ट बैरक के रूप में अपग्रेडेशन किया गया, जिसका अब उद्घाटन कर दिया गया है ।पुलिस कर्मियों के लिए अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त आदर्श बैरक के निर्माण का मुख्य उद्देश्य बैरक में रहने वाले पुलिसकर्मियों को स्वस्थ वातावरण प्रदान करना है,जिससे पुलिसकर्मी जब दिन भर की भाग-दौड़ एवं थकान भरी ड्यूटी से जब बैरिक में आराम करने आये तो उन्हें घर जैसी अनुभूति एवं पूर्ण सुविधा मिल सके और वे शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रह सकें। उक्त स्मार्ट बैरक में प्रत्येक पुलिसकर्मी के लिए स्टोरेज बेड, अलमारी, व्यक्तिगत सेल्फ की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। बैरक से अटैच बाथरूम, शौचालय उत्तम गुणवत्ता के बनवाए गए हैं। पूर्व में जनपद चमोली की समस्त पुलिस बैरकों का अपग्रेडेशन कर उन्हें भी पुलिस स्मार्ट बैरक के रूप में परिवर्तित किया जा चुका है। इस अवसर पर पुलिस उपाधीक्षक चमोली,प्रभारी निरीक्षक कोतवाली चमोली,प्रतिसार निरीक्षक,यातायात निरीक्षक व कोतवाली चमोली के समस्त पुलिसकर्मी मौजूद रहे।

आयुष्मान योजना में अब निःशुल्क उपचार के सत्यापन के बाद ही होगा क्लेम का भुगतान : स्वास्थ्य मंत्री

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आयुष्मान योजना के चतुर्थ वर्षगाँठ पर 23 सितम्बर, 2022 को आयोजित आरोग्य मंथन-4 में योजना के क्रियान्वयन को पारदर्शी बनाने हेतु प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. धन सिंह रावत द्वारा यह घोषित किया गया कि दिनांक 2 अक्टूबर, 2022 से रोगी के उपचारोपरांत लाभार्थी से सत्यापन प्रमाण-पत्र लिया जायेगा कि उपचार के हेतु चिकित्सालय द्वारा कोई भी धनराशि नहीं ली गयी है तथा उसका उपचार पूर्णत निःशुल्क किया गया है।

राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2022 को इस सम्बन्ध में सभी चिकित्सालयों को आदेश निर्गत कर दिये गये हैं। इस आदेश के अनुसार चिकित्सालयों द्वारा लाभार्थी के उपचारोपरांत क्लेम प्रस्तुत करते समय लाभार्थी का सत्यापन प्रपत्र तथा इसके अतिरिक्त चिकित्सालय का प्रमाण-पत्र दाखिल किया जाना अनिवार्य कर दिया गया है।सत्यापन प्रपत्र में लाभार्थी द्वारा यह सत्यापित किया जायेगा कि चिकित्सालय द्वारा योजना के अन्तर्गत निःशुल्क उपचार किया गया है, चिकित्सालय द्वारा उपचार हेतु कोई धनराशि नही ली गयी है तथा चिकित्सालय द्वारा बाहर से भी कोई दवाई अथवा उपचार सम्बन्धी अन्य सामग्री लाभार्थी से नहीं मंगायी गयी है। इस सत्यापन प्रपत्र में लाभार्थी यह भी बतायेगा कि उसे उपचार से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों (यथा डिस्चार्जसमरी, जांच/परीक्षण की रिपोर्ट्स, उपचार का बिल जो चिकित्सालय द्वारा क्लेम हेतु दाखिल किया जायेगा आदि) को चिकित्सालय द्वारा उपलब्ध करा दिया गया है।इस सत्यापन प्रपत्र में लाभार्थी यह भी प्रमाणित करेगा कि यह प्रपत्र उसके स्वयं (अथवा परिवार के सदस्य) द्वारा भरा गया है और चिकित्सालय के किसी स्टाफ द्वारा नहीं भरा गया है।प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश में लाभार्थी के सत्यापन प्रपत्र के अतिरिक्त चिकित्सालय द्वारा भी प्रमाण-पत्र दिया जायेगा कि लाभार्थी का पूर्णत निःशुल्क उपचार किया गया है तथा उपचार से सम्बन्धित सभी दस्तावेजों को भी उसे उपलब्ध करा दिया गया है। चिकित्सालय द्वारा इस प्रमाण-पत्र में यह भी बताया जायेगा कि डिस्चार्ज के पश्चात लाभार्थी को आवश्यकतानुसार 15 दिनों तक की अवधि की दवाईयाँ निःशुल्क उपलब्ध करा दी गयी हैं। चिकित्सालय द्वारा प्रमाण-पत्र में यह भी उल्लेख किया जायेगा कि लाभार्थी के उपचार पर कितना खर्च आया और अब 5 लाख रूपये के वॉलेट में कितनी धनराशि शेष है।

आदेश में चिकित्सालय के लिये यह भी अनिवार्य किया गया है कि उपचार की धनराशि के बिल पर लाभार्थी के हस्ताक्षर हों, तभी प्राधिकरण द्वारा क्लेम का भुगतान अनुमन्य होगा।प्राधिकरण द्वारा निर्गत आदेश के अनुसार चिकित्सालय द्वारा लाभार्थी को सत्यापन प्रपत्र की प्रति तथा चिकित्सालय के प्रमाण-पत्र की प्रति भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। यह नवीन व्यवस्था 2 अक्टूबर, 2022 से दाखिल किये जाने वाले क्लेम्स पर लागू होगी और प्राधिकरण द्वारा लाभार्थी के सत्यापन प्रपत्र तथा चिकित्सालय के प्रमाण-पत्र प्राप्त होने और यह सुनिश्चित करने के पश्चात कि लाभार्थी का पूर्णतया निःशुल्क उपचार हुआ है, चिकित्सालय को क्लेम का भुगतान किया जायेगा।

प्राधिकरण द्वारा लाभार्थी के सत्यापन प्रपत्र तथा चिकित्सालय के प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में की गयी इस नवीन व्यवस्था से जहाँ योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का सशक्तिकरण होगा, वहीं दूसरी ओर चिकित्सालयों को क्लेम्स का समय से शीघ्र भुगतान करने में भी सुविधा होगी। साथ ही, निःशुल्क उपचार के सम्बन्ध में किसी शिकायत की स्थिति भी उत्पन्न नहीं होगी। यह नवीन व्यवस्था योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन की दृष्टि से भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा।राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा दिनांक 28 सितम्बर, 2022 को निर्गत आदेश उपचार के उपरांत लाभार्थी के सत्यापन प्रपत्र तथा लाभार्थी के उपचार के उपरांत चिकित्सालय के प्रमाण-पत्र की प्रतियां संलग्न हैं

बचत खाते को लेकर डाक विभाग ने किया बड़ा बदलाव, जानें डिटेल्स

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

आप बैंक के बचत खाते की तरह ही डाकघर में बचत खाता खोल सकते हैं। हाल ही में डाक विभाग ने डाकघर बचत खाते से पैसे निकालने के नियमों में बदलाव किया है। ये नियम केवल 10,000 रुपये या उससे अधिक की राशि पर लागू होते हैं। संचार मंत्रालय के अनुसार 25 अगस्त को जारी सर्कुलर में डाकघर की किसी भी शाखा में बचत खातों से 10,000 रुपये या उससे अधिक की निकासी के लिए सत्यापन की आवश्यकता होगी। इन शाखाओं में कोई सत्यापन नहीं होगा, इसमें कहा गया है कि सिंगल हैंडेड डाकघरों से 10,000 रुपये और उससे अधिक की निकासी का सत्यापन समाप्त कर दिया गया है। 17 जुलाई 2018 के एक आदेश में केवल संबंधित शाखा डाकघरों में निकासी के लिए सत्यापन का सुझाव दिया गया है। हालांकि, हाल ही में पीओएसबी सीबीएस मैनुअल में नियम 64 के तहत एक नोट जोड़ा गया है।

मंडल प्रमुख कर सकेंगे विशेष जांच

इस अधिसूचना के अनुसार अंचल प्रमुख की यह विशेष जिम्मेदारी है कि सुरक्षा उपायों और धोखाधड़ी को रोकने के लिए हर आवश्यक प्रयास सावधानी पूर्वक किया जाए। सर्किल प्रमुख स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर कोई भी विशिष्ट जांच करने के लिए स्वतंत्र हैं जो वे करना चाहते हैं। इस सत्यापन का उद्देश्य बैंकिंग धोखाधड़ी की आशंकाओं को कम करना है।

खाताधारक एक दिन में 20,000 रुपये तक निकाल सकेंगे।

इसके अलावा डाक विभाग ने अपने ग्राहकों के लिए निकासी की सीमा भी बढ़ा दी है। नए नियम के तहत, खाताधारक ग्रामीण डाक सेवा की एक शाखा में एक दिन में 20,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। पहले यह सीमा 5,000 रुपये थी।

जानिए, कितना हो सकता है अधिकतम लेनदेन

इसके अलावा, कोई भी शाखा पोस्टमास्टर (बीपीएम) एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से अधिक के नकद जमा लेनदेन को स्वीकार नहीं करेगा। यानी एक दिन में एक खाते में 50,000 रुपये से अधिक का नकद लेनदेन नहीं किया जा सकता है।

जमा केवल चेक या निकासी फॉर्म के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे।

नए नियमों के मुताबिक, बचत खाते के अलावा अब पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF), सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS), मंथली इनकम स्कीम (MIS), किसान विकास पत्र (KVP), नेशनल डिपॉजिट इन सेविंग्स सर्टिफिकेट (NSC) स्कीम चेक या निकासी फॉर्म के माध्यम से स्वीकार किया जाएगा।इस योजना पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है, आपको बता दें कि डाकघर बचत योजना पर 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज मिलता है। डाकघर में बचत खाता खोलने के लिए आपको केवल 500 रुपये जमा करने होंगे। इसके बाद भी आपके खाते में 500 रुपये का न्यूनतम बैलेंस रखना जरूरी है। अगर आपके खाते में राशि 500 रुपये से कम है तो खाता रखरखाव शुल्क के रूप में 100 रुपये काट लिए जाएंगे।

संपादकीय

हर शहर का हो बेहतर नियोजन

बीते दिनों दिल्ली और आसपास के इलाकों में भारी बारिश के एक दिन के बाद ही पानी से भरी सड़कें, रेंगते यातायात, टूटे वाहन और घुटनों तक गहरे पानी में चलने वाले नागरिक जैसे परिचित दृश्य देखने को मिले. दो हफ्ते पहले बेंगलुरु में कई जगहों में भारी जलजमाव की स्थिति थी. ऐसी दुखद स्थितियां शहरी नियोजन की कमियों की तरफ इशारा करती हैं. नालियों की बेहतर निकासी क्षमता की कमी और झीलों व नदियों पर ध्यान न देने के साथ शहरी स्थानों को कंक्रीट में बदलने का जोर हर तरफ दिखता है. सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के अनुसार, बेंगलुरु जैसे शहर ने ईज ऑफ लिविंग इंडेक्स 2020 में क्वालिटी ऑफ लाइफ मेट्रिक के तहत सौ में से 55.67 स्कोर किया, राजधानी होने के बावजूद दिल्ली 57.56 तक पहुंचा, जबकि भुवनेश्वर का स्कोर सिर्फ 11.57 था. एक आदर्श दुनिया में यह स्थिति अस्वीकार्य है. पश्चिम में 1898 में एबेनेजर हॉवर्ड द्वारा चलाये गये गार्डन सिटी आंदोलन ने शहर के केंद्र में काम के माहौल को विकेंद्रीकृत करने की मांग की थी. नतीजतन, शहरों को योजनाबद्ध तरीके से डिजाइन किया गया. ऐसे आंदोलन इस विचार से प्रेरित थे कि कामगारों का जीवन स्तर बेहतर हो. अमेरिका में गार्डेन सिटी पड़ोस की अवधारणा के साथ विकसित हुआ, जहां एक स्थानीय स्कूल या सामुदायिक केंद्र के आसपास आवासीय घरों और सड़कों का आयोजन किया गया तथा यातायात कम करने और सुरक्षित सड़कें प्रदान करने पर जोर था. प्रदूषण और भीड़भाड़ पर नियंत्रण के साथ जैव विविधता बनाये रखने के लिए लंदन में चारों ओर एक महानगरीय हरित पट्टी है. सवाल है कि रिंग रोड और शहरी फैलाव से आगे भारतीय शहरों में ऐसा कुछ क्यों नहीं हो सकता है. पेरिस में '15 मिनट सिटी' का विचार काफी सरल है. इसके तहत हर पेरिसवासी को खरीदारी, कामकाज, मनोरंजन संबंधी जरूरतों को 15 मिनट की पैदल या बाइक की सवारी के भीतर पूरा करने में सक्षम होना चाहिए. इस सक्षमता का मतलब होगा कि वाहनों की आवाजाही काफी कम हो जायेगी. अगले कदम के रूप में पैदल यात्रियों के लिए बेहतर व्यवस्था देने की आवश्यकता है. बेंगलुरु को एक ऐसे शहर के रूप में फिर से डिजाइन क्यों नहीं किया जा सकता है, जहां यातायात की परेशानी न हो. क्या भोजन के लिए 10 मिनट की डिलीवरी के बजाय काम करने के लिए 10 मिनट की पैदल दूरी बेहतर नहीं होगी? प्रत्येक भारतीय शहर में आदर्श रूप से एक मास्टर प्लान होना चाहिए, जिसे एक-दो दशक के अंतराल पर अद्यतन किया जाए. इन योजनाओं में किफायती आवास पर ध्यान जरूरी है. देश में शहरी भूमि उपयोग को बेहतर करने की जरूरत है. सैटेलाइट इमेजरी को देखकर साफ लगता है कि रैखिक बुनियादी ढांचे के साथ धान के खेतों में पसरता जा रहा शहरी विकास अनौपचारिक, अनियोजित और विशाल पड़ोस के साथ खासा बेतरतीब है. सार्वजनिक भूमि उपलब्धता पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है. विश्व बैंक के अनुसार, 2050 तक नागरिकों का जीवन स्तर निराशाजनक करते हुए जलवायु परिवर्तन भारत के सकल घरेलू उत्पाद को तीन फीसदी तक कम कर सकता है. भारत के शहरों को अपनी प्राकृतिक तट रेखाओं और नदी के मैदानों की रक्षा कर, अतिक्रमणों को हटाकर भूमि पर बोझ कम करना शुरू करने की आवश्यकता है. बालू के टीलों की रक्षा करना और मैंग्रोव वनों को संरक्षित करना इस लिहाज से बेहद जरूरी होगा. सभी चालू और भावी शहरी बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर जलवायु परिवर्तन के परिप्रेक्ष्य से पुनर्विचार करने की आवश्यकता होगी.

पानी से भरी बाल्टी में डूबने से डेढ़ वर्षीय बच्ची की मौत, परिवार में मचा कोहराम

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

बाजपुर, 30 सितंबर। । ऊधम सिंह नगर में शुक्रवार को दिल दहला देने वाली घटना हो गई। इसने हर किसी को गम में डुबो दिया। जिले के बाजपुर में दोपहर के वक्त खेलते वक्त पानी से भरी बाल्टी में एक बच्ची गर गई, जिससे उसी बाल्टी में डूबने से उसकी मौत हो गई। बच्ची डेढ़ साल की थी। काफी देर बाद स्वजनों का ध्यान उधर गया तो उनमें कोहराम मच गया। घटना की सूचना पुलिस को नहीं दी गई है।

ग्राम महेशपुरा निवासी रूपबसंत सैनी की डेढ़ वर्षीय बेटी मानवी घर के आंगन में खेल रही थी। इसी बीच वह आंगन में रखी पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई और पानी से खेलने लगी। इसी दौरान वह अचानक बाल्टी में गिर गई और बाल्टी में भरे पानी में डूब गई। पिता रूपबसंत ने बताया कि वह अपनी सब्जी की दुकान पर गया था, जबकि उसकी पत्नी रानी घर की छत पर गोबर के उपले बनाने के लिए गई थी। परिवार की अन्य महिलाएं कुछ दूरी पर स्थित दूसरे घर में काम करने गई थी, जबकि भाई मजदूरी करने के लिए बाहर गए थे। इसी बीच मेरी डेढ़ वर्षीय बेटी मानवी खेलते हुए आंगन में पानी से भरी बाल्टी के पास पहुंच गई और बाल्टी में गिर गई। पास में सो रहे बड़े भाई देव ने जब उठकर देखा तो उसकी बहन बाल्टी में पड़ी थी।

रूपबसंत ने बताया कि बेटे देव ने तुरंत अपनी मां को सूचना दी और मां ने आकर मासूम बच्ची को अचेतावस्था में बाल्टी से बाहर निकाला, जिसे आनन फानन में ही अस्पताल ले जाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हादसे से परिवार में मातम छाया हुआ है। अचानक बेटी की मौत के बाद से सदमे में पहुंची मां का रो-रो कर बुरा हाल है।

उत्तराखंड रोडवेज बस में महिला से छेड़खानी, चालक को लोगों पीटा, हल्द्वानी पहुंचकर मांगी माफी

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

हल्द्वानी, 30 सितंबर। उत्तराखंड परिवहन निगम के एक चालक की वजह से पूरे महकमे की बदनामी हो रही है। हरियाणा मार्ग पर चलने वाली बस में सवार महिला यात्री संग उसने छेड़खानी कर दी। पता चलते ही यात्रियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। हल्द्वानी पहुंचने पर मामला पुलिस के पास पहुंच गया। आरोपित गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगने लगा। लिखित तहरीर नहीं मिलने और माफीनामे पर पुलिस ने चालक को छोड़ दिया। वहीं, मामले को लेकर एआरएम का कहना है कि पुलिस से रिपोर्ट लेने के बाद चालक पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

काठगोदाम डिपो की एक बस गुरुवार रात हिसार से हल्द्वानी के लिए चली थी। बस में करीब 40 लोग सवार थे। स्टाफ के तौर पर नियमित चालक और विशेष श्रेणी का परिचालक था। इस बीच चालक ने परिचालक को स्टेयरिंग थमा दी और खुद महिला यात्रियों के पास जाकर बैठ गया। आरोप है कि इस दौरान उसने महिला यात्री के साथ छेड़खानी शुरू कर दी। इस बात का अन्य यात्रियों को पता लगने पर उन्होंने चालक को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद हल्द्वानी पहुंचते ही पुलिस को फोन कर दिया। जिसके बाद मय वाहन चालक को कोतवाली लाया गया। यहां माफीनामे के बाद उसे छोड़ दिया गया। वहीं, एआरएम सुरेश चौहान का कहना है कि पुलिस से पूरे मामले की रिपोर्ट मिलने पर विभाग कार्रवाई करेगा।

बनभूलपुरा से किशोरी लापता

इधर एक अन्य मामले में बनभूलपुरा थाना क्षेत्र में रहने वाली रहने एक 16 वर्षीय लड़की संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई। मामले में उसकी दादी ने गुमशुदगी दर्ज कराई है। महिला ने बताया कि 27 सितंबर से पोती लापता है। वहीं, किशोरी के लापता होने को लेकर स्वजनों ने गौलापार स्टेडियम के पास रहने वाले एक युवक पर शक भी जताया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।

देहरादून में फर्जी तरीके से रह रहा था नाइजीरियन, कोर्ट ने सुनाई छह साल की सजा

देहरादून, 30 सितंबर। । बिना पासपोर्ट व वीजा के धर्म परिवर्तन कर प्रेमनगर क्षेत्र में रह रहे एक नाइजीरियन को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय संजय सिंह की अदालत ने छह वर्ष की सजा सुनाई है।

15 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया

सहायक अभियोजन अधिकारी सोमिका अधिकारी ने बताया कि आठ जून 2010 को कैंट कोतवाली पुलिस भारतीय सैन्य अकादमी में पासिंग आउड परेड की सुरक्षा को लेकर शहर में सत्यापन अभियान चलाया। केहरी गांव में भी सत्यापन अभियान चलाया गया।

संदिग्ध व्यक्ति से की पूछताछ

इस दौरान गांव में एक संदिग्ध दिखाई दिया। एलआइयू के कर्मचारी राममूर्ति सिंह की ओर से कार्यालय में इसकी सूचना दी गई। इसके बाद विदेशी शाखा प्रभारी एसआइ बृजमोहन सिंह गुसाईं व एसआइ लक्ष्मण सिंह मौके पर पहुंचे और संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ की।

खुद को नाइजीरिया का निवासी बताया

इस पर उसने खुद को नाइजीरिया का निवासी बताया, जिसके बाद एलआइयू उसे कार्यालय लेकर आई और दोबारा पूछताछ की। इस दौरान उसने अपना नाम एलविस सिंबो टटोंग बताया और कहा कि उसने नंदा की चौकी निवासी मधु क्षेत्री के साथ वर्ष 2007 में कोर्ट मैरिज की थी।

पहचान छिपाने के लिए उसने शादी के दौरान कोर्ट में ईसाई से हिंदू धर्म परिवर्तन का शपथ पत्र दिया था। वह एलआइयू को पासपोर्ट व वीजा की कापी भी नहीं दिखा पाया। उसने विदेशी पंजीकरण कार्यालय में अपने निवास की सूचना भी नहीं दी थी। इस मामले में राममूर्ति सिंह रावत की तहरीर पर आरोपित एलविस सिंबो टटोंग के विरुद्ध आठ जून 2010 को मुकदमा दर्ज किया गया।

सजा पूरी होने पर नाइजीरिया छोड़ने के आदेश

करीब 12 वर्ष बाद अदालत ने एलविस सिंबो टेटोंग को दोषी मानते हुए छह वर्ष की कैद और 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि सजा की अवधि पूरी होने के बाद दोषी को उसके देश में छोड़ने के आदेश दिए हैं।

क्या है पीएम मोदी का चीता चैलेंज? आप भी आजमाइए किस्मत

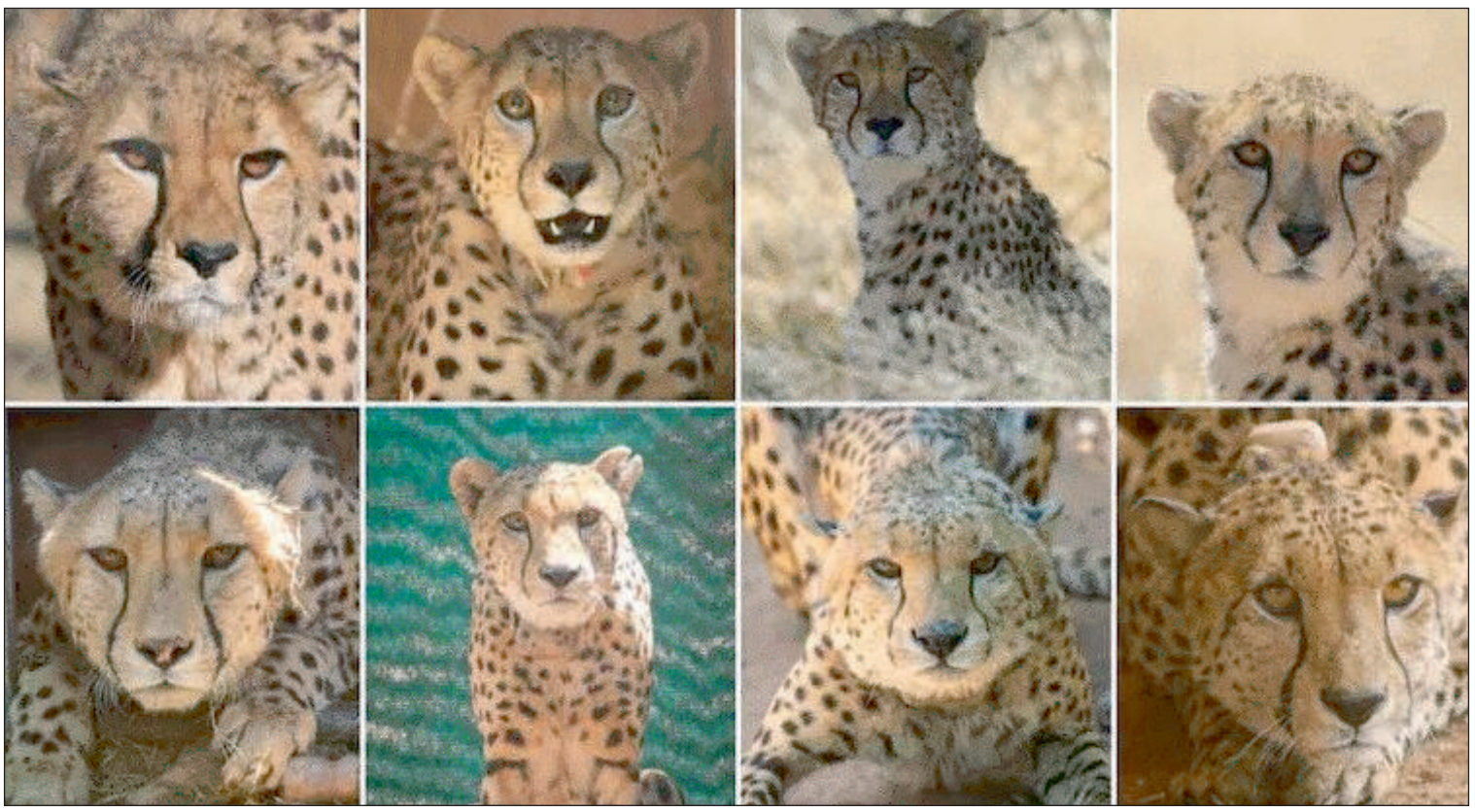

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

ब्यूरो रिपोर्ट, 30 सितंबर। भारत की धरती पर जब से ये 8 चीते नामीबिया से लाए गए हैं, तब से लोगों में इन्हें देखने की उत्सुकता बढ़ गई है। हर कोई इन्हें दूर से एक बार देखना चाहता है, लेकिन अभी सबसे पहली प्राथमिकता इनकी देखरेख को लेकर है, जिसकी वजह से इन्हें पर्यटकों से दूर रखा जा रहा है।

हां, अगर आप सच में इन्हें देखना चाहते हैं, तो सरकार आपके लिए एक प्रतियोगिता लेकर आई है। इसमें आपको चीतों के नाम देने होंगें, जानवरों के साथ अच्छा व्यवहार करने का महत्व बताना होगा और चीता प्रोजेक्ट का नाम देना होगा। वैसे, जबसे ये प्रतियोगिता शुरू हुई है, तब से लोगों में चीतों को नाम देने की उत्सुकता जगी है, कोई इनका नाम मिल्खा दे रहा है, तो कोई चेतक, वायु, स्वस्ति और त्वारा जैसे नामों का सुझाव दे रहा है। चलिए आपको इन तीन प्रतियोगिता के बारे में अच्छे से बताते हैं।

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में आठ चीतों को छोड़ा गया है। भारत में चीतों के विलुप्त होने के कई दशकों के बाद, 'भारत में चीतों के परिचय के लिए कार्य योजना' इकोसिस्टम में संतुलन बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण पहल साबित हुई है। इस पहल के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर, 2022 को अपने मन की बात में नागरिकों से इस प्रोजेक्ट के लिए नाम सुझाने की बात कही थी। अगर आपके दिमाग में इस प्रोजेक्ट को लेकर कोई नाम आता है, तो mygov.in वेबसाइट पर जाकर अपने सुझाव दें और कुनो नेशनल पार्क में चीतों को देखने का मौका पाएं।

सुझाव देने की आखिरी तिथि : 26 अक्टूबर, 2022 रात 11:45 बजे तक है।

काठगोदाम रोडवेज डिपो को मिलेगा आइएसबीटी का दर्जा, परिवहन मंत्री चंदन राम दास का एलान

बागेश्वर,30 सितंबर। कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास ने कहा है कि सभी रोडवेज डिपो को आधुनिक बनेंगे। शीघ्र काठगोदाम डिपो को आइएसबीटी (ISBT) का दर्जा मिलेगा। दास शुक्रवार को इंटर कालेज गागरीगोल के चार नए कक्षा-कक्षों का लोकार्पण कर रहे थे। इस दौरान दास ने विद्यालय को पांच लाख रुपये देने की घोषणा की।

कैबिनेट मंत्री दास ने कहा कि सरकार शिक्षा की बेहतरी को काम कर रही है। शिक्षा के मंदिरों से बेहतर समाज का निर्माण होता है। शिक्षक ही अच्छे समाज व राष्ट्र का निर्माता हैं। उन्होंने अन्य मदों से धनराशि की व्यवस्था करने का भरोसा दिया। कहा कि एमएसएमइ के माध्यम से स्वरोजगार की शिक्षा दी जाएगी।

परिवहन निगम 350 करोड के घाटे में चल रहा था। गत माह पूरे घाटे से उभार दिया है। परिवहन निगम के कर्मचारियों को नियमित वेतन दिया जा रहा है। सभी डिपो को आधुनिक डिपो बनाया जाएगा। शीघ्र काठगोदाम डिपो को आइएसबीटी का दर्जा दिया मिलेगा।

जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव ने हाईटेक शौचालय बनाने की घोषणा की। विद्यालय के प्रबंधक दीपक पाठक ने अतिथियों का स्वागत किया। छात्र-छात्राओं ने रंगारंग कार्यक्रम पेश किए। संचालित विज्ञान वर्ग की वित्तीय स्वीकृति का शासनादेश कराने का आग्रह भी किया।

इस दौरान भाजपा जिलाध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट, निवर्तमान प्रधानाचार्य नंदन सिंह अल्मिया, ब्लाक प्रमुख हेमा बिष्ट, सदस्य जिला पंचायत गोपाल सिंह, जनार्जन लोहनी, मुख्य विकास अधिकारी संजय सिंह, उपजिलाधिकारी राजकुमार पांडे, मुख्य शिक्षा अधिकारी जीएस सौन, राजेंद्र टंगड़िया, हरीश ऐठानी, जीतेंद्र तिवारी आदि मौजूद थे।

यह भवन 24.53 लाख रुपये की लागत से बने। विद्यालय में कक्षा-कक्षों के निर्माण के लिए 15 लाख सांसद निधि और 9.53 लाख रुपये खनन न्यास निधि में प्रदान की गई थी।

अंकिता भंडारी हत्याकांड के महत्वपूर्ण विषयों पर राज्यपाल से चर्चा की

न्यूज़ वायरस नेटवर्क

उत्तराखंड बाल संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष उषा नेगी द्वारा महामहिम राज्यपाल महोदय से उत्तराखंड की बेटी अंकिता भंडारी हत्याकांड में कुछ महत्वपूर्ण विषयों , को लेकर चिंता व्यक्त की गई ! जांच में कुछ महत्वपूर्ण बिंदु को भी शामिल किए जाने का अनुरोध किया गया !उषा नेगी द्वारा महामहिम राज्यपाल को यह भी अवगत कराया गया की उत्तराखंड में नशे का जिस तरह से , व्यापार चल रहा है वह कई घटनाओं को जन्म दे सकता है जिसमें ड्रग्स , सुल्फा , गांजा तो आम है , किंतु अन्य सिंथेटिकड्रग्स द ड्रग्स द केमिकल पर कई किस्म का नशा बच्चों को उसका आदि बना रहा है छोटी-छोटी बच्चियों को इस धंधे में उतारा जा रहा है इस पर रोक लगाने की आवश्यकता है !इस अवसर पर साधारण तरीके से 1 दिन की मुख्यमंत्री किताब का विमोचन महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा किया गया ! यह एक बहुत ही सुंदर पहल थी किताब को लिखने का उद्देश्य था महिलाओं की सशक्त राजनीतिक भूमिका नारी सशक्त होगी तभी समाज भी सशक्त होगा ! इस किताब को बहुत सुंदर तरीके से लिखा गया कुसुम रावत द्वारा !

दैनिक
न्यूज वायरस

न्यूज़ वायरस नेटवर्क प्रा. लिमिटेड, मेरठ के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक मौ. सलीम सैफी द्वारा विश्वनाथ प्रिंटर्स, अजबपुर कलां, देहरादून से मुद्रित एवं 48/3 बलबीर रोड, डालनवाला, देहरादून (उत्तराखंड) से प्रकाशित।

सम्पादक :
मौ. सलीम सैफी
कार्यकारी सम्पादक
आशीष तिवारी
दूरभाष : 0135-2672002

email-dainiknewsvirus@gmail.com
RNI No.- UTTHIN/2012/44094

वाद-विवाद का न्याय क्षेत्र देहरादून न्यायालय मान्य होगा